वॉटर, टेली कम्यूनिकेशन, बैंकिंग, सीवेज और बाकी सारी सुविधाएं उस ग्रोथ सैंटर में विकसित हों, इसके लिए यह दस करोड़ की राशि उनको दी जाती है इस योजना को आगे बढ़ाने के लिए, उद्योग को आकर्षित करने के लिए वहां की राज्य सरकार और वहां काम करने वाली जो एजेंसियां हैं, उनकी जवाबदेही होती है कि उस क्षेत्र को ज्यादा से ज्यादा विकसित करें। हम यह राशि बेसिक इन्फ्रास्ट्रक्चर को डैवलप करने के लिए देते हैं।

*382. *[The Questioner (Shri Ananta Sethi) was absent for answer vide page 24infra.]*

*383. *[The Questioner (Shri P. Prabhakar Reddy) was absent, for answer vide page 27infra.]*

*384. *[The Questioner (Shri S.S. Ahluwalia) was absent, for answer vide page 27infra.]*

Allocation of diesel oil to Rajasthan

*385. SHRI SANTOSH BAGRODIA: Will the Minister of PETROLEUM AND NATURAL GAS be pleased to state:

(a) whether Government have allocated diesel oil to Rajasthan;

(b) if so, the details thereof; and

(c) the quantity of diesel oil supplied to Rajasthan during the last three years?

THE MINISTER OF PETROLEUM AND NATURAL GAS (SHRI RAM NAIK): (a) and (b) Diesel Oil is supplied through Oil Marketing Companies to meet the full market demand.

(c) The following quantities of diesel oil were supplied to the State of Rajasthan during last three years:—

Year	Quantities in TMT
1997-98	2,420
1998-99	2,557
1999-2000	2,687

SHRI SANTOSH BAGRODIA: There is a continuous complaint about supply of diesel; probably, all over the country, but I am confining my question

to Rajasthan. I want to mention about two things; quality and quantity. Whenever we visit different areas all over Rajasthan, the only problem about petroleum products, which include diesel, is that neither the quality nor the quantity reaches the consumers for which they are paying for. I would like to know from the hon. Minister whether they have any scheme to take full responsibility for any transit losses and al) for the quality and charge only for the proper quality and quantity supplied at the destination points.

श्री राम नाईक: सभापति जी, जहां तक क्वालिटी का सवाल है, यदि किसी को लगता है कि मुझे जो क्वालिटी मिली है, वह सही नहीं है तो वह शिकायत कर सकता है। मौटे तौर पर मेजर डिपो से जब ग्राहक के यहां या पैट्रोल पंप पर डीजल जाता है, तो रास्ते में कुछ मिलावट होती है, ऐसी शिकायतें हैं कि उसमें कैरोसीन या नाफता या सॉलवैंट मिलाए जाते हैं, ऐडल्ट्रेशन होता है। इस प्रकार की क्वालिटी की शिकायतों के बारे में हमने काफी कुछ काम किया है, कई जगह पर रेड्स डाली हैं लेकिन उसके अलावा भी हमने जून में दो ऑडर्स निकाले हैं। एक नाफता के संबंध में और दूसरे अन्य सॉल्वेन्ट्स के बारे में कि इसके आगे उनको लाईसेंस लेना पड़ेगा और कुल मिला कर गए तीन-चार महीनों में जो प्रक्रिया हमने चलाई है, उसके आधार पर ऐडल्ट्रेशन में कुछ मात्रा में कमी हुई है। सारे देश का यदि मैं कह दूं तो सारे देश में पेट्रोल का कंजम्पशन 10 परसेंट बढ़ा है। इसका मतलब है कि adulteration has been reduced to that extent. गुजरात जैसे राज्य में प्रिवेंशन ऑफ ब्लैक मार्केटिंग ऐक्ट के तहत कुछ लोगों को, 40-42 लोगों को डीटेन किया गया है। तो गुजरात का पेट्रोल कंजम्प्शन 19 परसेंट बढ़ा है और इसलिए समय-समय पर ....(व्यवधान)....

श्री संतोष बागड़ोदिया: राजस्थान का भी बताइए।

श्री राम नाईक: राज्यों का 13 परसेंट है। आपने जनरल बात की, मैं जनरल बात बता रहा हूं और इसलिए ऐडल्ट्रेशन के विरोध में ...(व्यवधान)...

श्री सभापति: यह राजस्थान का सवाल है।

श्री राम नाईक: ऐडल्ट्रेशन के विरोध में हमने सारे देश में इस प्रकार की प्रक्रिया चलाई है और जहां तक क्वांटिटी की शॉर्टिज है, राजस्थान में कहीं भी क्वांटिटी की शॉर्टिज मेरे ख्याल में नहीं है। यदि माननीय सदस्य यह बता दें कि यहां-यहां इस प्रकार की उनको शिकायत आई है तो मैं उसका ख्याल रखूंगा। जितनी आवश्यकता डीजल की है, सारे राजस्थान को वह उनकी आवश्यकता के अनुसार दिया जाता है। जहां कम हो गया होगा, यदि माननीय सदस्य मुझे बताएं तो हम दे देंगे।

SHRI SANTOSH BAGRODIA: Sir, my second supplementary is this. The hon. Minister has just now mentioned that there is an increase of 10 per cent

in the consumption of petrol all over the country and that is the reason why adulteration has gone done. I really do not understand as to what is the relation between the increase in consumption and adulteration. Part (b) of my supplementary is that Rajasthan, after the reorganisation of States of U.P., Bihar and Madhya Pradesh, is the biggest State in the country. Sir, many areas in Rajasthan are border areas and are inaccessible. People in these areas, in connivance with the Government officers, company officials, dealers, transporters and local Government officials, from time to time, create an artificial shortage, say, once or twice in a year. Will the hon. Minister ensure that these areas are specially catered to so that the artificial shortages—for example, in Barmer, etc.—which are created, could be stopped? There is always some problem or the other in remote areas with regard to supply of diesel. Will the Minister kindly look into it? Thank you.

श्री राम नाईक: सभापति जी, यह बात सही है कि जितने पेट्रोल पम्प देश में सब जगहों पर हैं या राजस्थान में भी जितने होने चाहिए, उतने नहीं हैं। इस समय राजस्थान में 1048 पेट्रोल पम्प हैं और हमने नए 196 पेट्रोल पम्प देने का निश्चय किया है। उस काम को करने के लिए जो डीलर सलेक्शन बोर्ड होते हैं, राजस्थान के लिए ऐसे तीन बोर्डों का रीऑर्गेनाइजेशन किया गया है और उन बोर्डों ने अभी अपना काम शुरू किया है। अखबारों में नए आउटलेट्स के लिए ऐप्लिकेशन्स के ऐडवर्टाइजमेंट आने शुरू हुए हैं और इस भूमिका के जरिए यह जो काम है....गए तीन-चार साल में नए पेट्रोल पम्प डीलर सलेक्शन बोर्ड के जरिए नहीं दिए गए थे, किसी न किसी कारण से कुछ बैकलॉग रह गया है लेकिन हम यह काम जल्दी पूरा करेंगे और जो नए डीलर सेलेक्शन बोर्ड बने हैं, उसके जो चेयरमैन हैं, वह सामान्यत: हाईकोर्ट के या सेशन कोर्ट के रिटायर्ड जज हैं। 25 दिसम्बर को हमने देश में कुल मिला कर 57 नए बोर्ड बनाए हैं, उनके अध्यक्षों की मीटिंग मैंने बुलाई है और उनसे मैं यह आग्रह करूंगा कि यह काम उन्हें जल्दी से जल्दी पूरा करना चाहिए ताकि राजस्थान और साथ ही साथ सारे देश में हम जो 2101 नए पेट्रोल पम्प बनवाने जा रहे हैं, वहां लोगों को जल्दी से जल्दी पेट्रोल और डीज़ल मिल सके।

श्री रामदास अग्रवाल: सभापति, महोदय, माननीय मंत्री जी ने बताया है कि डीज़ल की सप्लाई 1997-98 में 2400 टी.एम.टी. थी, वह 1999-2000 में बढ़कर 2687 टी.एम.टी. हो गई। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि यह जो बढ़ोतरी हो रही है, यह डिमांड जो आपने पूरी की, क्या आप डिमांड भी प्राप्त करते हैं किसी स्टेट से? राजस्थान से क्या आपने प्रति वर्ष डिमांड भी प्राप्त की और उसके अगेंस्ट में आपने सप्लाई की या डिमांड नहीं आती है, केवल आप सप्लाई करते हैं, जैसे-जैसे पेट्रोल पम्प मांगते रहते हैं? इसका कोई आधार तो बनाया हुआ होगा कि फलां स्टेट ने इतना डीज़ल मांगा, उसके अगेंस्ट में हमने इतना डीज़ल दिया है, फलां स्टेट ने इतना केरोसीन मांगा

है, उतना केरोसीन हमने दिया है, फलां स्टेट ने इतनी गैस मांगी है, उतनी गैस हमने दी है। क्या इसकी जानकारी आप हमें उपलब्ध करा सकेंगे?

श्री राम नाईक: सभापति जी, पेट्रोल पम्प के अलावा कुछ डायरेक्ट कंज्यूमर्स होते हैं, फैक्ट्रीज और कारखानों में काम करने के लिए, उनको डीजल चाहिए। राजस्थान में ऐसे डायरेक्ट यूज करने वाली 301 यूनिट्स हैं। उनकी आवश्यकता के अनुसार हम दे रहे हैं। जैसा मैंने पहले कहा कि जहां पर कमी आती है, यदि मुझे इसकी जानकारी मिली तो मैं उसे पूरा करूंगा। देश में डीज़ल की शार्टेज नहीं है इसलिए जो मांगता है, उसको दिया जाता है।

श्री नरेन्द्र मोहन: सभापति महोदय, पेट्रोल उत्पाद के वितरण के बारे में मंत्री जी ने जो जानकारी दी है, वह अपने आप में ठीक है लेकिन उसमें कुछ बातें उठ खड़ी हुई हैं। मंत्री जी को स्मरण होगा कि पिछले दिनों देश में कई जगह पैट्रोल वितरण करने वालों ने स्ट्राइक कर दी थी और कुछ समय के लिए पैट्रोल मिलना बन्द हो गया था। ऐसा लग रहा था कि इससे बड़ी आफत आ जाएगी। राजस्थान भी इस समस्या से गुजरा है। यह ठीक है कि नए पैट्रोल पम्प स्थापित करने की योजना है। हमारे यहां डीज़ल की कमी नहीं है लेकिन प्रश्न यह है कि निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र के बीच में जो समस्याएं हैं, विशेषरूप से सार्वजनिक क्षेत्र की जो समस्या है, वह यह है कि आए दिन एक धमकी दी जाती है कि हम पैट्रोल उत्पाद का वितरण बंद कर देंगे। अगर कहीं कोई ऐसी स्थिति आई तो उससे निपटने के लिए मंत्री के पास क्या योजना है? क्या राजस्थान में या देश में कहीं किसी निजी कम्पनी ने पैट्रोल पम्प खोलने के लिए कोई आवेदनपत्र दिया है, यदि दिया है तो क्या आप कोई अनुमति देने जा रहे हैं?

श्री राम नाईक: जहां तक पहला प्रारंभिक सवाल है, इसके लिए मैं यह जरूर कहना चाहूंगा कि कई जगह पैट्रोल पम्प ऐसोसिएशन के लोगों ने हड़ताल पर जाने की धमकी दी है। स्वाभाविक है कि जब हम मिलावट के विरोध में अभियान चला रहे हैं तो हर एक को पिंच होता है। लेकिन एसोसिएशन के अधिकृत लोग जब मेरे पास आते हैं। तो कहते हैं कि आप जो कर रहे हैं वह ठीक है। हम एडल्ट्रेशन करने वालों के प्रतिनिधि नहीं है। मैं मानता हूं कि इंडस्ट्रीज की ऐसी कोई समस्या नहीं है। लेकिन एक समस्या है कि एडल्ट्रेशन में जहां 5-6 रुपए में कैरोसीन बाहर मिलता है उसका वह एडल्ट्रेशन करते हैं, 16-17 रुपए डीज़ल की कीमत होती है तो मुनाफा कम होता है। जिन लोगों को इससे पिंच होता है, वे कुछ लोग ऐसा करते रहते हैं। लेकिन इंडस्ट्री के आधार पर सामान्यत: पैट्रोल डीलर्स एसोसिएशन जो काम कर रहे हैं, उससे वे सहमत हैं, ऐसा मैं मानता हूं।

श्री नरेन्द्र मोहन: क्या निजी क्षेत्र ने राजस्थान या किसी और जगह पैट्रोल पम्प खोलने की अनुमति मांगी है, और मांगी है तो इस बारे में क्या स्थिति है? यह नीतिगत प्रश्न है।

श्री राम नाईक: वर्ष 2002 तक जो 5 एडमिनिस्टर्ड प्राइसेस हैं, जैस डीजल, एलपीजी, पैट्रोल, कैरोसीन और एविएशन ट्रबाइन फ्यूअल, इनकी मार्केटिंग सरकार के पब्लिक सैक्टर अंडरटेकिंग के माध्यम से करनी है, ऐसा नीतिगत फैसला हुआ है। उसी फैसले पर हम चल रहे हैं। यदि किसी ने इस प्रकार की एप्लीकेशन दी होगी तो मैं उनको उत्तर दूंगा। आपके पास यदि कोई और जानकारी हो तो मुझे जरूर बताएं।

श्री नरेन्द्र मोहन: एक रिलाइन्स ने आपसे मांगी है और अनुमति देने के बारे में शायद विचार कर रहे हैं।

श्री राम नाईक: मेरे से ज्यादा जानकारी उनके पास दिखाई देती है। इस प्रकार का कोई भी विवाद, इस समय हमारे विचाराधीन नहीं है।

SHRI N.K.P. SALVE: Sir, *inter alia* the hon. Minister has stated that the new mechanism he has evolved for checking adulteration appears to be efficacious and effective because petrol consumption has increased by 10 per cent. This is an extremely pedestrian way of getting satisfied with the new mechanism. He is not only a good man, but he is a good accountant also. Therefore, I would like to ask him whether there is any method by which he can ask the distributors to submit their accounts to him in terms of which their input and output can be verified.

श्री राम नाईक: सभापति महोदय, इन्होंने पहला रिमार्क जो मेरे बारे में दिया कि मैं पेडेस्ट्रियन वे में जबाव दे रहा हूं तो मैं इसे एक कोम्प्लिमेंट मान रहा हूं क्योंकि मेरे पास खुद की गाड़ी नहीं है बल्कि एक मंत्री होने के नाते सरकार की गाड़ी मिली है इसलिए मैं एक पेडेस्ट्रियन भी हूं। मैं अपने अनुमान के आधार पर यह कहना चाहता हूं कि जो मिलावट करते और बेचते है वे मिलावट का कोई एकाउण्ट नहीं रखते। आप तो एकाउण्ट में स्वयं माहिर है आप तो जानते होंगे।

श्री एन.के.पी. साल्वे: कितना पैट्रोल खरीदा और कितना बेचा?

श्री राम नाईक: यही दिखाया जाता है कि जितना खरीदा उतना ही बेचा। जितनी मिलावट की जाती है उसके बेचने और मिलावट का कोई एकाउण्ट नहीं दिखाया जाता है। Sir, there are two systems of accounting. मिलावट करने वालों का अलग एकाउण्ट होता है about which normally nobody knows.

श्री सूर्यभान पाटील वहाडणे: सभापति महोदय, माननीय मंत्री जी ने कहा है कि जिस राज्य से डिमांड आती है वह पूरी की जाती है। मैं प्रक्रिया के बारे में पूछना चाहता हूं। भारत देश के कई पिछड़े भाग हैं जैसे असम, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम आदि। वहां विकास का एक प्रोजेक्ट, एक पैकेज केंद्र की ओर से चालू हुआ था। इस पैकेज में सभी चीजें आती हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि इसमें अभी तक डीजल, पैट्रोल के लिए क्या किया गया है? क्या इसके अनुसार इनकी डिमांड पूरी होगी?

श्री राम नाईक: इस पैकेज के अनुसार पेट्रालियम मंत्रालय ने काम किया है। असम और नॉर्थ-ईस्ट के क्षेत्रों में भी शोध कार्य हम तीव्र गति से कर रहे हैं। इन्होंने डिस्ट्रिब्यूशन की जो बात कही, राजस्थान के बारे में मैंने कहा था कि वहां हम कुछ अधिक पैट्रोल पम्प बना रहे हैं। ठीक यही व्यवस्था हम नॉर्थ-ईस्ट के लिए भी कर रहे हैं। इससे पहले नॉर्थ-ईस्ट में सेपरेट डीलर सिलेक्शन बोर्ड नहीं था। हमने नॉर्थ-ईस्ट में सेपरेट सिलेक्शन बोर्ड बनाया है जिससे वहां के फैसले अन्य राज्यों से पहले होंगे और इसका लाभ नॉर्थ-ईस्ट राज्यों को मिलेगा।

*386. *[The Questioner (Shri Brahmakumar Bhatt) was absent, for answer vide page 29 infra]*

*387. *[The Questioner (Shri Sukhdev Singh Libra) was absent, for answer vide page 29 infra.]*

Impact of globalisation

*388. SHRI SWARAJ KAUSHAL: Will the Minister of COMMERCE AND INDUSTRY be pleased to state:

(a) what is the impact of globalisation on the domestic industry, agriculture and employment in the country; and

(b) what is the basis of Government's findings and conclusions in this regard?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY (DR. RAMAN): (a) and (b) A Statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) and (b) The impact of globalization on domestic industry, agriculture and employment in the country has been analyzed in various issues of Economic Survey, Plan Documents of Planning Commission and other reports of the Government. The summary conclusions which emerge from these reports reveal the following:

* Globalization and economic liberalization has enhanced competition, increased economic efficiency and augmented productivity of the domestic industry. As a result the industrial sector which recorded an average annual compound growth rate of 4.6% from 1970-71 to 1979-80 and 6.6% from 1980-1981 to 1989-90 achieved a high growth rate of 7.3% in Eighth Plan (1992—97).